दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 30 अगस्त 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 333

महत्वपूर्ण एवं खास

मैनपुरी : बारिश की वजह से 16 साल पुराने मकान का लैंटर गिरा, 3 महिलाएं की मृत्यु

मैनपुरी (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक दर्दनाक हादसे में तीन महिलाओं की जान चली गई। लगातार हो रही बारिश के कारण एक 16 साल पुराने मकान का लैंटर गिर गया, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और राहत दल को दी, जो मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने में जुट गए। एडीएम रामजी मिश्रा ने कहा, सुबह 8:15 बजे ये घटना घटी है...तीनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। सत्य प्रकाश शर्मा (डिप्टी एसपी) ने कहा, यहां रह रहे एक यादव के परिवार पर लैंटर गिर जाने से 3 महिलाएं की मृत्यु हो गई। ये घटना बारिश की वजह से हुआ है, 15-16 साल पुराना मकान था। तो ये लैंटर आज सुबह अचानक से गिर गया है। जांच जारी है।

बांग्लादेश में आफत, भयानक बाढ़ से 31 लोगों की मौत

ढाका । बंगलादेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 31 तक पहुंच गई है और 58 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी बंगलादेशी समाचार पोर्टल डेली ऑब्जर्वर ने दी है। बुधवार को ली ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को लगभग 3,80,000 डॉलर पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। भारतीय मीडिया ने पहले रिपोर्ट दिया था कि बंगलादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य त्रिपुरा में बाढ़ से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 17 लाख अन्य लोग प्रभावित हुए। मॉनसून की शुरुआत में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार मॉनसूनी बारिश हुई, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुईं और संपत्ति और कृषि भूमि को नुकसान हुआ।

अमेरिका में लिस्टेरिया बीमारी से 8 की मौत, 50 से अधिक बीमार

लॉस एंजेलिस । अमेरिका में लिस्टेरिया बीमारी से 8 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की है। लिस्टेरिया एक ऐसा जर्म है जो मांस और खाद्य पदार्थों में फ्रिज के तापमान पर भी रह सकता है। सीडीसी के अनुसार, इस बीमारी के लक्षण कुछ लोगों में दिखने में कम से कम 10 सप्ताह तक का समय ले सकता है। महामारी विज्ञान, प्रयोगशाला और ट्रेसबैक डेटा से पता चलता है कि काटे गए मांस, जिसमें बोअर हेड ब्रांड लिवर बुर्स्ट भी शामिल है, लिस्टेरिया से दूषित हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं। लिस्टेरिया रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में आसानी से फैलता है। जैसे, हाथों और भोजन के माध्यम से आसानी से फैलता है। लिस्टेरिया संक्रमण के कारण कुल 57 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब तक आठ मौतें हो चुकी हैं। लिस्टेरिया से बीमार होने का जोखिम सबसे अधिक गर्भवती महिलाओं में होता है या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। इस बीमारी से बचाव के लिए कटे हुए मांस को खाने से बचने का सुझाव दिया गया है। नई मौतों में दक्षिण कैरोलाइना में दो और फ्लोरिडा, टेनेसी और न्यू मैक्सिको में एक-एक मौत शामिल है। इलिनोइस, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी इस प्रकोप से मौतें हुई हैं। यूएस कृषि विभाग के अनुसार, बोअर हेड ब्रांड ने 30 जुलाई तक 71 विभिन्न मांस और पोल्ट्री उत्पादों के 7 मिलियन पाउंड से अधिक उत्पाद वापस मंगाया है।

फर्जीवाड़ा रोकने को केंद्र का बड़ा फैसला: अब यूपीएससी उम्मीदवारों की आधार कार्ड से होगा वेरिफिकेशन

नई दिल्ली । आरएनएस

केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को पंजीकरण के समय और परीक्षाओं के कई चरणों के दौरान उम्मीदवारों की पहचान को सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित पहचान पत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यूपीएससी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय और परीक्षा/भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान के वेरीफाई के लिए स्वैच्छिक आधार पर ऑथेंटिकेशन करने की अनुमति है, जिसके लिए हां/नहीं या/और ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग किया जाएगा।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) अधिनियम के सभी प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' से जारी निर्देशों का पालन करेगा। यह महत्वपूर्ण कदम जुलाई में यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 की उम्मीदवार पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को रद्द करने और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के बाद उठाया गया है।

यूपीएससी परीक्षा में 821वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल करने वाली प्रोविजनल आईएएस अधिकारी खेडकर पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उन पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें यह दावा भी शामिल है कि पुणे पोस्टिंग के दौरान उन्होंने अलग केबिन और स्टाफ की मांग की, वाशिम जिले में अप्रत्याशित स्थानांतरण का सामना किया और लाल-नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर बिना अनुमति के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के सामने वाले कक्ष पर कब्जा कर लिया, बिना सहमति के कार्यालय के फर्नीचर को हटा दिया और अनधिकृत सुविधाओं का अनुरोध किया।

यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, समूह 'ए', भारतीय जैसी सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण) आयोजित करता है। इसमें सिविल लेखा सेवा, समूह 'ए', भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, समूह 'ए', भारतीय रक्षा लेखा सेवा, समूह 'ए', भारतीय रक्षा संपदा सेवा, समूह 'ए', भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ए', भारतीय डाक सेवा, समूह 'ए', भारतीय पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा, समूह 'ए' शामिल हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया था। खेडकर ने जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास हासिल करने के लिए अपनी पहचान गलत बताई थी।

ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलेगा 3 करोड़ तक का पुरस्कार

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान

रायपुर । आरएनएस

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। यह घोषणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह के दौरान की गई, जहां विभिन्न खेल विधाओं के 502 प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और 1 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि वितरित की गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि जशपुर और रायगढ़ में 105 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और नवा रायपुर में 62 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम और सिंथेटिक फुटबॉल मैदान विथ रनिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य में पहली बार आवासीय हॉकी अकादमी शुरू की गई है, और जल्द ही बालिकाओं के लिए फुटबॉल अकादमी भी स्थापित की जाएगी।मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से अपील की कि वे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपनी खेल प्रतिभा को निखारें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें।

जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कार्यवाई, मुठभेड़ में मार गिराए तीन आतंकी; घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश

जम्मू । आरएनएस

जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिले के बुधल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार सेना ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 2 राजौरी में और एक कुपवाड़ा में बॉर्डर के पास मारा गया। अभी इनके शव बरामद नहीं हुए हैं। ये खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे।

अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि खेरी मोहरा लाठी गांव और दंथल इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार रात को तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस ने कहा, तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने खेरी मोहरा इलाके के पास सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई।

पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को उस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कई आतंकवादी और उनके कमांडर मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान भी हताहत हुए हैं।

पुंछ और राजौरी जिलों तक सीमित आतंकवादी गतिविधियां अब जम्मू के अन्य क्षेत्रों में फैल रही हैं, ऐसे क्षेत्र जो कुछ साल पहले तक इस तरह की घटनाओं से मुक्त थे जैसे कि चिनाब घाटी, जिसे आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था। उधमपुर और कठुआ को भी आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था। आतंकवादी वाहनों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और ग्रेनेड के साथ-साथ एम4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

झारखंड में कांस्टेबल बहाली के लिए दौड़ लगाते 25 अभ्यर्थी बेहोश, 583 पदों के लिए एक लाख से ज्यादा युवा लगा चुके हैं दौड़

रांची । आरएनएस

झारखंड के आबकारी विभाग में कांस्टेबल नियुक्ति के लिए गिरिडीह न्यू पुलिस लाइन में कराई जा रही दौड़ के दौरान गुरुवार को 25 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इसके पहले बुधवार को भी 19 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई थी और उनमें से कई बेहोश हो गए थे। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

गुरुवार को बेहोश हुए अभ्यर्थियों में कोडरमा के विजय यादव एवं आनंद कुमार, पलामू के सुहैल अख्तर एवं प्रभु कुमार, लोहरदगा के प्रमोद उरांव, गिरिडीह के सचिन वर्मा एवं दिनेश तुरी, बिहार के औरंगाबाद निवासी अंकित कुमार, अरवल निवासी रंजन कुमार, धनबाद के प्रकाश विश्वकर्मा, विशाल महतो, अभिषेक उपाध्याय, देवघर के गुड्डू कुमार एवं अन्य शामिल हैं। इन सभी को एंबुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया।

बता दें कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद आबकारी विभाग में कांस्टेबल की नियुक्ति की परीक्षा पहली बार हो रही है। इसके पहले संयुक्त बिहार में वर्ष 1980 में इस विभाग में कांस्टेबलों की नियुक्ति हुई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जा रही परीक्षा के जरिए कुल 583 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए विभिन्न जिलों में शारीरिक जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। कड़ी धूप में इतनी लंबी दौड़ लगाने में कई अभ्यर्थी बीमार या बेहोश हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में आयोजित दौड़ में गिरिडीह जिला स्थित केशवारी निवासी एक अभ्यर्थी पिंटू कुमार की मौत हो गई थी। अन्य जिलों में भी दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थियों के बीमार या बेहोश होने की खबरें आ रही हैं।

इस परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, लेकिन परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों में हजारों लोग पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं। अब तक करीब एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल हो चुके हैं।

आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को मिलता रहेगा लाभ, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

श्रीनगर । आरएनएस

जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। निजी अस्पताल मरीजों को इलाज देने से मना नहीं कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज न मुहैया कराने का निर्णय लिया था। कहा था कि आगामी 1 सितंबर से ये सुविधा निजी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होगी। अस्पतालों के इस फैसले का जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी अस्पतालों से कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की व्यवस्था जारी रखें। दरअसल, निजी अस्पतालों ने हाल में एक फैसला किया। इस फैसले में कहा गया है कि उन पर कई करोड़ रुपये का बकाया इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है, जो उन्हें नहीं चुकाया गया है। जिसकी वजह से अस्पतालों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की। साथ ही निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह अस्पतालों में मरीजों को इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के तहत देते रहें।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कार्ड धारकों को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के निवासियों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों को सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (ईएचसीपी) के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाना है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पात्र परिवारों की परिभाषित श्रेणियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया।

ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत सरकार ने 250 अस्पतालों को जोड़ा है। इनमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, 69.85 लाख लाभावन्तिों को पंजीकृत किया गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के लिए साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की थी।

पैन कार्ड के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली । आरएनएस

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी 'पहचान प्रमाण पत्र' को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि भारत संघ ने सैद्धांतिक रूप से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार इसे लेकर नियमों में भी स्पष्टता लाने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र ने सभी मांगों को स्वीकार किया

पीठ ने कहा, 'याचिका के लंबित रहने के दौरान, हमने भारत संघ से जवाब मांगा, जो इस मामले में बहुत सहायक रहा है और मोटे तौर पर उन्होंने वर्तमान याचिका में उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6/7 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।' ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 और 7 पहचान प्रमाण पत्र और लिंग में परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित हैं।

क्या है मामला- दरअसल एक ट्रांसजेंडर ने साल 2018 में याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसके पैन को आधार से जोडने का प्रयास विफल हो गया है क्योंकि पैन कार्ड में आधार कार्ड के विपरीत कोई 'तीसरा लिंग' का विकल्प नहीं है। बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह केंद्र को निर्देश दें कि वह पैन कार्ड पर तीसरे लिंग की अलग श्रेणी का विकल्प बनाएं, ताकि उनके जैसे ट्रांसजेंडर लोग इसे आधार से जोडक़र 'सटीक पहचान प्रमाण पत्र' प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि आधार प्रणाली में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद तीसरे लिंग की श्रेणी को शामिल किया गया और उन्होंने आधार में ट्रांसजेंडर के रूप में पंजीकरण कराया।

पीएम मोदी को इस्लामाबाद में एससीओ बैठक के लिए भेजा गया न्योता : पाकिस्तान विदेश कार्यालय

इस्लामाबाद

पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि की कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर के मध्य में इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने अपने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्र प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है।

उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने पहले ही बैठक में भाग लेने की पुष्टि कर दी है। बलूच ने कहा, इसकी जानकारी उचित समय पर दी जाएगी कि किस देश ने बैठक में हिस्सा लेने की पुष्टि की है।

पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करने वाला है। इस बैठक से पहले मंत्रिस्तरीय बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी, जो एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर केंद्रित होंगी।

ऐसी उम्मीद है कि पीएम मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल नियुक्त कर सकते हैं। पहले भी, एससीओ सीएचजी बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व मंत्रियों द्वारा किया गया है और इस बार भी यही पैटर्न होने वाला है।

पीएम मोदी इस साल 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के 24वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अस्ताना में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी बैठक के लिए पाकिस्तान आएंगे।

राजनीतिक विश्लेषक कामरान यूसुफ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य सभी सदस्य देशों को निमंत्रण देना एक प्रोटोकॉल है, जिसका पालन कोई भी मेजबान देश करता है। पाकिस्तान ने भी यही किया है। मैं इसे राजनीतिक स्टंट के रूप में नहीं देखता। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी इस्लामाबाद आएंगे, मैं इसा नहीं सोचता।

पिछले वर्ष पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे।

चंपई के इस्तीफे से खाली हुई कैबिनेट सीट पर रामदास सोरेन बनेंगे मंत्री

- आज 11 बजे आयोजित किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह

रांची । आरएनएस

हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद उनकी जगह घाटशिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री की ओर से रामदास सोरेन को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए राजभवन को पत्र भेज दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार 30 अगस्त को दिन के 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

इधर, चंपई सोरेन भी इसी दिन औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।

रामदास सोरेन ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए सीएम हाउस से फोन आया है। चंपई सोरेन के जिम्मे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और जल संसाधन विभाग थे। संभावना जताई जा रही है कि रामदास सोरेन को ये दोनों विभाग दिए जाएंगे।

चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से राज्य के कोल्हान प्रमंडल में सियासी समीकरण प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के फैसले को सियासी 'डैमेज कंट्रोल' की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 61 वर्षीय रामदास सोरेन भी चंपई सोरेन की तरह संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीति भी कोल्हान प्रमंडल में केंद्रित रही है। वह घाटशिला से दो बार विधायक चुने गए हैं।

उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन सीएम बनाए गए थे। फिर, करीब पांच महीने बाद जब हेमंत सोरेन जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए तो उसके छठे दिन 4 जुलाई को ही चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया था और हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार में चंपई सोरेन मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन वह नाराज चल रहे थे। उन्होंने 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनसे अपमानजनक तरीके से सीएम पद से इस्तीफा लिया गया।